मछली खोजने और उन को पकड़ कर बाहर भेजने के लिए यह सब काम किया जा रहा है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का साफ उत्तर नहीं आया। अभी तक पिछली सरकार ने बड़े लोगों को लाइसेंस दिया है, तो नयी सरकार भविष्य में इस की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी, इस की गारन्टी देगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बड़े लोगों को भी लाइसेंस कुछ देने पड़ते हैं क्यों कि इस में बड़े जहाज काम में आते हैं जो दो सौ मील की दूरी पर जा कर मछली पकड़ते हैं। वह खास किस्म के जहाज होते हैं जो कुछ बाहर से भी मंगाए जाते हैं और कुछ यहां भी बनाए जाते हैं। छोटे मछेरों का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इस बात की तरफ बड़ी तवज्जह है सरकार की कि छोटे मछेरों को कोई नुकसान न हो और उन की आमदनी में कुछ इजाफा हो।

Building of Foodgrains Storage by Non-Government Agencies

*511. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Food Corporation of India has offered to utilise private and non-Government agencies in building fresh storage facilities for foodgrains; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). The Food Corporation of India have launched a scheme to encourage construction of godowns by private and other agencies on their own lands for letting them out to the Corporation. Some feature of the scheme are given below:—

(a) Godowns are to be built by private parties etc. as per the specifications of F.C.I. for being let out to the Corporation on guaranteed occupation basic of 3 to 5 years.

(b) The rent ceiling fixed in such cases is 40 paise per sq. ft. per month for rural areas and 50 paise per sq. ft. per month for urban areas.

(c) The banks have agreed to give loans to such private parties at concessional rate of interest of 11 per cent as soon as the site and other conditions are approved by F.C.I.

(d) So far, the F.C.I. has executed agreement with private parties for 71.97 lakh tonnes.

SHRI K. LAKKAPPA: What was the estimate of loss sustained out of exposing foodgrains without any storage facilities? What is the requirement of funds for construction of godowns in the country?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We have been constructing storage facilities, that is the FCI has been constructing, with the aid of World Bank, the capacity proposed to be built is about 3.2 million tonnes; we have encouraged private parties also to construct further capacity.

SHRI K. LAKKAPPA: My question is: what was the estimated loss without storage facilities in the whole of India? What is the financial requirement for construction of godowns in the country?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The loss estimated in storage last year, that is 1976-77, is 0.6 per cent.

SHRI K. LAKKAPPA: Not storage, lack of storage. What is the loss?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The total loss is 0.6 per cent.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, allowing the private parties to construct godowns will always lead to certain

speculations and it is only encouraging and patronising the affluent people in the cities and there will also be abuse of power. What action is going to be taken by this Ministry to have their own godowns instead of patronising the private parties by giving them huge amount of money by way of bank facilities, etc?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, this scheme was visualised by the previous Ministry. Anyhow, this is the only method, I would submit, to have the required storage capacity immediately. In fact, the Government of India is not in a position to spend so much of money for this purpose. We are having contracts for three to five years only for the time being and we are trying to construct more godowns ourselves also with the aid of other Agencies like the World Bank, etc.

श्रीमती मृणाल गोरे : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले सरकार की यह नीति थी कि खानगी पार्टीज को इस प्रकार के गोडाउन्स के कांस्ट्रक्शन के लिए इजाजत मिले और उनको बैंक से सुविधा मिलने वाली थी तथा कम इन्ट्रेस्ट पर पैसा मिलने वाला था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता क्या यह उचित नहीं होगा कि इसके बजाये स्वयं एफ सी आई या दूसरी सरकारी एजेंसियां स्वयं इस काम को अपने हाथ में ले लें ? मैं यह भी जानना चाहती हूं गए 3–4 साल में, इस निर्णय के बाद क्या किसी खानगी पार्टी ने इस प्रकार के गोडाउन तैयार किए हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मई, 1977 तक तकरीबन एक लाख टन कैपेसिटी के गोडाउन तैयार करके दिए हैं जिनका कब्जा ले लिया गया है ।

श्रीमती मृणाल गोरे : भाड़ा कितना देना पड़ा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने पहले सवाल के जवाब में बतला दिया है कि कितना भाड़ा देना पड़ा । बाकी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एफ सी आई और स्टेट एजेंसीज अपने गोडाउन बनायें । वह जल्दी से जल्दी बनते जा रहे हैं और प्राइवेट एजेंसीज का काम कम होता चला जा रहा है ।

श्री किरंगी प्रसाद : मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि 6 परसेंट की हानि हो रही है । ऐसा देखा गया है कि जहां क्रय सेन्टर खाद्यान्नों के लिए खोले गए हैं वहां पर बरसात भी होती है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर क्षति न हो उसके लिए कोई वैकल्पिक उपचार की व्यवस्था है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां खुले में डालना पड़ा उसके लिए पालिथीन के कैप इस्तेमाल किए गए । स्टोरेज के लिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कवर स्टोरज का इन्तजाम किया जाये ।

SHRI SONU SINGH PATIL: These non-Government Agencies are charging very heavily. They think it to be a chance for making windfall profit. Area-wise you are paying 59 paise per foot-carpet area and it is too high a rent. Have you examined the economics of this scheme of the previous Government?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: They have to provide the land as also the platform for that. This was treated to be a proper rent for them.

SHRI S. R. DAMANI: I would like to draw the attention of the hon. Minister to my question No. 154, to which the reply was given on 13th June 1977 and the Minister has stated therein that 5½ million tonnes of foodgrains were stored for 1½ years in the *kutcha* godowns and only 3.67 lakh tonnes in the *pucca* godowns. I would like to know from the hon. Minister whether this figure remains the same or there is any change in it.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I do not have that answer just now before me, but I would submit that these are the facts. FCI has covered godown capacity of 58.57 lakh tonnes and hired capacity of 32.55 lakh tonnes including CWC and SWC.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह अनुभव करती है कि देश में इस समय जितना अनाज स्टोरेज करने की आवश्यकता है, उसको अपने यहां स्टोरेज करने के लिए जो भण्डार बनाने की आवश्यकता है उतना सरकार बना चुकी है, और फालतू भण्डार प्राइवेट स्टोरेज में अगर उन को रखना है तो उस में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इसलिए ऐसा करने की बजाय रूस से जो दो मिलियन टन गेहूं लोन पर लिया हुआ है, उस को क्यों न वापस कर दिया जाए। इस पर क्या सरकार विचार करेगी ताकि यहां पर स्टोरेज करने का खर्च बच जाए ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास जरूरत से कम है और रूस से जो दो मिलियन टन गेहूं लिया हुआ है उसे वापस करने पर विचार हो रहा है और गेहूं के बदले गेहूं ही वापस कर दिया जाए, ऐसा सोचा जा रहा है।

डा० सुशीला नायर : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि .06 परसेन्ट अनाज का नुकसान हुआ है। अब अगर इन के पास 20 मिलियन टन अनाज है तो 200 लाख टन का .06 परसेन्ट 1 लाख 20 हजार टन हो जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि एक साल में जो 1 लाख 20 हजार टन अनाज बर्बाद हुआ है, उस का कितना दाम होगा और उस से कितने गोदाम आप बना सकते हैं ? आप ने कुछ अर्थशास्त्र का हिसाब लगा कर देखा है कि हर साल जो इतना नुकसान होता है, उस को बचाने के लिए आप कितने समय में अपने गोदाम बनाएंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्या ने सारा हिसाब लगा कर बताया है, यह बड़ा अच्छा किया है। मैं बताना चाहता हूं कि शायद पिछली सरकार को यह ख्याल नहीं होगा कि इतने सारे अनाज के स्टोरेज की जरूरत पड़ जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, काफ़ी कवर्ड स्टोरेज बना लें ताकि जो नुकसान होता है, उस से बचा जा सके।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उन के पास जो वेगन्स हैं उन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और पूरे देश में तकरीबन 20 हजार वेगन्स सरप्लस हो जाएंगे। क्या मंत्री महोदय इस तरफ़ ध्यान देंगे कि जब तक उन वेगन्स को काम में नहीं लाया जाता, स्टोरेज परपजेज के लिये उन वेगन्स के लिए उन का इस्तेमाल करें ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे दोस्त को शायद इस बात का पता नहीं है कि गेहूं ले जाने के लिए भी कवर्ड वेगन्स काफ़ी नहीं मिल रहे हैं। आज तो हालत यह है कि गेहूं ले जाने के लिए भी वेगन्स पूरे नहीं हैं क्योंकि हम दूसरे सूबों में इतना ज्यादा गेहूं ले जा रहे हैं। हमें कवर्ड स्पेस नहीं मिल रही है। अभी तक तो स्कूलों में छुट्टियां थीं, इसलिए वहां पर हम ने काफ़ी गेहूं डाल दिया था। इस के अलावा गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और दूसरी जगहों पब्लिक प्लेसेज में भी हमने गेहूं रखा हुआ है। जहां कहीं भी हमें कवर्ड स्पेस मिली है, वहीं हम ने गेहूं डाल दिया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि गोदामों के अन्दर अनाज की अधिक हानि चूहों से होती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो नये गोदाम बनने जा रहे हैं या जो गोदाम किराये पर लिये जा रहे हैं उन गोदामों के बनाने वालों को कोई ऐसा सुझाव या हिदायत या डिजाइन दिया

है कि इन गोदामों के अन्दर चूहे न जा सकें। लाखों चूहे पता नहीं कितना गेहूं खा जाते हैं लेकिन इन चूहों से गेहूं की हानि को बचाने के लिए क्या कोई सुझाव दिया गया है जिस से वे इन गोदामों के अन्दर न जा सकें ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो एफ० सी० आई० ने स्पेसिफिकेशन तय किये हैं उसमें इस बात की कोशिश की गयी है कि चूहे न आ सकें। इसके बावजूद भी चूहे आ सकते हैं। हम बड़े बड़े अच्छे घर बनाते हैं लेकिन उनमें भी चूहे घुस ही जाते हैं।

श्री राम सेवक हजारी : मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि व्यापार मण्डल के मकान हैं, कोआपरेटिव सोसायटीज के मकान हैं, वे खाली पड़े रहते हैं, कुछ खास व्यक्ति उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्राथमिकता न देकर उन्हें अनाज रखने के लिए क्या किराये पर लेने की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आनरेबल मेम्बर कहीं भी कोई जगह बतायेंगे कि जगह खाली है, वह हम लेने को तैयार हैं।

श्री युवराज : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितना अनाज सरकारी गोदामों, गैर-सरकारी गोदामों और कितना अनाज आसमान के नीचे है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एफ० सी० आई० का अनाज अपने गोदामों में 58.57 लाख टन है और जो गोदाम किराये पर लिये हुए हैं उनमें 32.5 लाख टन है। शेष सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग, स्टेट वेयर हाऊसिंग एवं राज्य सरकार के गोदामों में है। 79 लाख टन कैप केपेसिटी भी है।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Sir, the Central Government is encouraging the private people also and they are giving money. Is there any stipulation that they have to give these godowns at a fixed rent? Is there any stipulation in their giving money to the private persons that they have to give the godowns at a particular rate of rent?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We do not give any money to the private persons. They get it from the banks and specifications have been provided. They have to prepare the sheds according to those specifications.

श्री जगेश्वर सिंह : मंत्री महोदय ने बताया कि गोदामों के अभाव में हर साल अनाज खराब हो जाता है। क्या सरकार की जानकारी में है कि बहुत सी सरकारी इमारतें अक्सर खाली रहती हैं ? राष्ट्रपति भवन है, राज्यों में राजभवन हैं, इनमें कुछ हिस्से खाली पड़े रहते हैं। क्या सरकार ऐसी सरकारी इमारतों में अनाज रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : गल्ले का काम ऐसा है, जो लोग इसका काम करते हैं, वे जानते हैं कि इसे कैसे मकानों में रखना चाहिए। अच्छे से अच्छे मकानों में रखने पर भी कुछ न कुछ हिस्सा अनाज का खराब हो जाता है। कुछ रोडेंट ले जाता है, कुछ को कीड़ा लग जाता है। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि राष्ट्रपति भवन में गल्ला रख दिया जाए।

SHRI K. SURYANARAYANA: Sir, the Minister has said that .6 per cent is the average loss on account of damages. I want to know the figures for various storage systems, *i.e.*, covered godowns and uncovered godowns and what is the percentage which they have lost in *pucca* godowns and the uncovered godowns. I want to know the separate figures which the Government has got.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: For this I require separate notice. It is a long question.